डा. हर्ष वर्धन: सर, अभी इस पर्टिकुलर योजना के तहत राशि को इससे ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार के मरीज हैं, जिनको और ज्यादा खर्चे की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारी राशियां है, जैसे आरोग्य निधि है, Prime Minister's Relief Fund है और ऐसे ही एम्स वगैरह में डायरेक्टर्स वगैरह के पास discretionary funds हैं और दूसरे कई सारे mechanisms हैं, जिनसे हम इस प्रकार के मरीजों की चिंता कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 228.

Initiatives to control the problem of anaemia

*228. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to National Family Health Survey (NFHS)-IV (2015-16), the prevalence of anaemia among women aged 15 to 49 years is 53.1 per cent;

(b) whether it is also a fact that after having taken a lot of initiatives in the last 49 years to control the problem of anaemia in the country by the previous and current Governments, the problem has remained unsolved; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes.

(b) and (c) The anemia control programme review indicated challenges in Iron Folic Acid supply chain management, demand generation and monitoring. Considering, the slow progress *i.e.* less than 1% per annum in reduction of anaemia from 2005 to 2015, the Government of India has launched the Anaemia Mukt Bharat (AMB) strategy under the Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nourishment (POSHAN) Abhiyaan and the targets has been set to reduce anaemia by 3% per year.

The 6x6x6 strategy under AMB implies six age groups, six interventions and six institutional mechanisms. The strategy focuses on ensuring supply chain, demand

generation and strong monitoring using the dashboard for addressing anaemia, both due to nutritional and non-nutritional causes.

(i) The six population groups under AMB strategy are:–

- Children (6-59 months)
- Pre-school children (5-9 years)
- Adolescents girls and boys (10-19 years)
- Pregnant women
- Lactating women
- Women of Reproductive Age (WRA) group (15-49 years)

(ii) The six interventions are:–

- Prophylactic Iron and Folic Acid Supplementation
- Deworming
- Intensified year-round Behaviour Change Communication (BCC) Campaign and delayed cord clamping
- Testing of anaemia using digital methods and point of care treatment
- Mandatory provision of Iron and Folic Acid fortified foods in Government funded health programmes
- Addressing non-nutritional causes of anaemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis and the six institutional mechanisms.

(iii) The six institutional mechanisms are:–

- Inter-ministerial coordination
- National Anemia Mukt Bharat Unit
- National Centre of Excellence and Advanced research on Anaemia Control
- Convergence with other ministries
- Strengthening supply chain and logistics
- Anaemia Mukt Bharat Dashboard and Digital Portal- one-stop shop for Anaemia.

This comprehensive strategy is expected to yield positive results in Anaemia control.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अंदर ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी है। वे एनीमिया से पीड़ित हैं। लगातार 50 साल की कोशिश के बाद, एक परसेंट वार्षिक दर से घटने के बाद भी इस बीमारी से 53 परसेंट महिलाएं पीड़ित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कोई विशेष कारण है? क्या किसी विशेष स्टडी से पता चल सकता है कि हिन्दुस्तान के अंदर महिलाओं में और बच्चों में खून की इतनी कमी क्यों है? क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी स्टडी इसके संबंध में कराने का निर्णय लिया है?

डा. हर्ष वर्धन: सभापति महोदय, इसके संबंध में तो हर जगह पर लगातार अध्ययन हो रहा है, लेकिन जो बेसिक सवाल पूछा गया है, वह यह है कि सरकार ने इस विषय को 2015 के अंदर बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि पिछले 50 साल से लगातार देखा गया है कि सभी सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी एनीमिया का जो incident है, वह 50 और 60 परसेंट के बीच में ही लगातार हर एज ग्रुप के अंदर चल रहा था। इसलिए अभी एनीमिया मुक्त भारत और पोषण अभियान के माध्यम से हर एज ग्रुप में छोटे बच्चे पांच साल तक के, पांच साल से नौ साल तक के, adolescent girls and boys, pregnant women, women of reproductive age group, इन सबके लिए स्कीम के तहत...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you have to be brief and crisp.

DR. HARSH VARDHAN: We are trying our best कि आने वाले सालों में कम से कम तीन परसेंट की इम्प्रूवमेंट हर साल हो।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, ज्यादातर खून की कमी गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों के अंदर मिलती है। हिन्दुस्तान के अंदर गरीबी बहुत है। क्या आंगनवाड़ी के माध्यम से और बाकी संस्थाओं के माध्यम से उनके लिए संतुलित आहार का कोई प्रबंध करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है कि उनको पोषक आहार मिल जाए, ताकि उनमें खून की कमी न रहे और उन बच्चों की संतुलित ग्रोथ हो सके?

डा. हर्ष वर्धन: सर, पिछले साल ही सरकार ने बहुत बड़ा National Nutrition Mission लॉंच किया है। इसके तहत खाली वुमन एवं चाइल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि उसके साथ एचआरडी मिनिस्ट्री और हैल्थ मिनिस्ट्री भी है और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। साल में "पोषण माह" और "पोषण पखवाड़ा" भी आयोजित होता है। जो मील है, जो पौष्टिक आहार है, वह तो ऐसे एरियाज़ में दिया ही जाता है। इसके साथ-साथ लोगों को लगातार आयरन की फोलिक एसिड की टेबलेट्स और supplementation of Iron and Folic Acid fortified food लगातार दिया जा रहा है। लोगों को ट्रीट करने की दृष्टि से, लोगों को

[डा. हर्ष वर्धन]

एजुकेट करने की दृष्टि से काम हो रहा है। पिछले साल ही, खाली एक साल में हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री ने छः लाख से ज्यादा कैम्प्स लगाये हैं।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, the supplementary that I wanted to ask has already been put by Mr. Gupta.

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है कि ट्राइबल वुमन सबसे ज्यादा एनीमिया की शिकार होती हैं। क्या सरकार ऐसा कोई सब-प्लान जारी कर रही है, जिसके कारण ट्राइबल वुमन, जो एनीमिया की शिकार है, उसे दूर किया जाए?

डा. हर्ष वर्धन: सभापति महोदय, सरकार की योजना सारे देश के लिए है। पिछले सालों में हमने केवल एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल ऑफिसर्स बनाये थे। हमने देश भर के स्टेक होल्डर्स की National Training Workshop की थी। हम लोग अभी करीब 13 स्टेट्स में स्टेट लेवल की वर्कशाप कर चुके हैं। आपने ट्राइबल एरियाज़ की बात कही है, ऐसे जो एरियाज़ हैं, खासकर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहां पर तकलीफ ज्यादा है, वहां पर और भी ज्यादा फोकस हैं, ध्यान है। सरकार ने 15 aspirational districts में पिछले सालों में जो काम किया, उनमें यह सुनिश्चित किया कि जो सबसे पिछड़े हुए हैं, उन पर सबसे ज्यादा सरकार ने ध्यान दिया और उनके parameters को improve किया। हमने इसके लिए पूरे समाज को involve किया है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 229. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

*** 229.** *[The Questioner was absent.]*

'Selling of electoral bonds in bearer form'

*229. DR. SANTANU SEN: Will the Minister of FINANCE be please to state:

(a) whether the Ministry was aware of the fact that the Reserve Bank of India (RBI) was against the decision of selling electoral bonds in bearer form;

(b) the list of reasons stated by RBI against the same in the meeting convened on October 11, 2017 and other communications; and

(c) why did Ministry take such a step inspite of the RBI's disapproval of the scheme, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the House.